



Research Ambition

An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer-reviewed & Open Access) Journal home page: www.researchambition.com
ISSN: 2456-0146, Vol. 07, Issue-I, May 2022



बच्चों के विरुद्ध अपराध एवं संबंधित विधियों पर सामाजिक एवं विधिक अध्ययन (Social and Legal Studies on Crimes Against Children and Related Laws)

Nitin Madhwani^{a,*} 

^aResearch Scholar (Law), Career Point University, Kota, Rajasthan, (India)

KEYWORDS

बच्चों के विरुद्ध अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराधों के सम्बन्ध में भारतीय विधिक दृष्टिकोण, अपराधों के कारण, घर में अपराध घर के बहार अपराध, स्कूलों में अपराध।

ABSTRACT

वर्तमान में मानव समाज प्रगति के साथ-साथ अनेक जटिल समस्याओं से भी गुजर रहा है। इन समस्याओं में प्रमुख समस्या 'अपराध' को कह सकते हैं क्योंकि आज का समय भागदौड़ भरी जिंदगी से ओत प्रोत हो गया है। जिस कारण से लोग अपनी रोजी रोटी जुटाने के लिए ही सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। अक्सर परिवारों में पुरुष व महिलायें दोनों ही काम काजी होते हैं। जिसकी बजह से परिवार व अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और इनके बच्चे अधिकतर रोजमर्रा के काम काज अकेले ही करते हैं जैसे कि स्कूल जाना, टयुशन या कोचिंग क्लास जाना बाजार से सब्जी व अन्य राशन लाना इत्यादि शामिल होता है। इन बच्चों को अकेला देख बाहरी असमाजिक तत्वों द्वारा इनको पहले हमदर्दी दिखाकर उनके साथ दोस्ती करके अपराधों को अंजाम दे देते हैं। जब इन परिवारों के साथ कोई अपराध घटित हो जाता है तो वे उन अपराधों की वजह से कुछ रोजमर्रा की जिन्दगी से हार मानकर टूट जाते हैं और यहाँ तक की कुछ लोग मानसिक विकसित भी हो जाते हैं। कई बार इन परिवारों के साथ में बच्चें ही अधिकतर शिकार होते हैं। क्योंकि ये अपरिपक्व समझ के होने के कारण बाहरी दुनिया को ठीक से समझ नहीं पाते और परिवार के सदस्यों को ठीक से बता भी नहीं पाते हैं। मानव समाज ने जितना विकास मानव सभ्यता को विकसित करने में किया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नए-नए आयाम को छुआ है। लेकिन फिर भी अपराधों को रोकने में नाकाम रहे हैं, भले ही सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर लागू कर दिया हो फिर भी अपराधों को रोकने में नकाम रहे हैं। इस शोध पत्र के माध्यम से बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के सम्बन्धों में विधियों का अध्ययन कर समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना है।

प्रस्तावना

बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के विषय में यदि आँकड़ों पर एक नजर डाले तो अपराधों में वृद्धि के ही आँकड़े नजर आते हैं। जब कि अपराधों को रोकने के लिए वर्तमान में संसाधनों को भी राज्य सरकारों द्वारा बढ़ाया गया है। नई तकनीकी उपकरणों का भी उपयोग किया जा रहा है लेकिन बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों का आँकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर देखा जाए तो जितनी तरक्की मानव समाज ने की है उसी हिसाब से अपराधों के नए-नए रूप भी सामने आये हैं। जिनमें समाज व बच्चों के प्रति हाने वाले अपराध चाहे वह अलग-अलग तरह से ही क्यों ना किये जा रहे हो जैसे धन संपत्ति से संबंधित अपराध या फिर महिलाओं से संबंधित अपराध और सबसे प्रमुख है बच्चों के प्रति अपराध इन अपराधों को रोकने के लिए कोई एक देश ही नहीं लगभग विश्व के सभी देश अनेक उपाय कर रहे हैं फिर भी अपराधों पर पूर्णता लगाम नहीं लगाई जा पा रही है। आज भी अपराधियों द्वारा नए-नए तरीके ढूँढ कर के कानूनों को ताक पर रखकर अपराधों को अंजाम दिया जाता है। जबतक पुलिस प्रशासन सक्रिय होता पाता है तब तक अपराधियों द्वारा अपराधों को अंजाम देकर कहीं गुम हो जाते हैं। कई बार पुलिस प्रशासन द्वारा शक्ति करने पर कुछ अपराधियों का पकड़ भी लिया जाता है तो सबुतो के अभाव में न्यायालयों द्वारा बरी भी हो जाते हैं। अब सबाल ये आता है कि अपराधों पर लगाम कैसे लगाई जाये।

बच्चों के विरुद्ध होने अपराधों के सम्बन्ध में परिकल्पना

अधिकतर आपने और हमने सबने सुना है कि बच्चें हमेशा मन के सच्चे होते हैं। फिर भी कुछ असमाजिक तत्वों के द्वारा बच्चों के विरुद्ध अपराध क्यो किये जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है।

बच्चों के विरुद्ध होने अपराधों के प्रमुख कारण

बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के कई कारण हो सकते हैं। बच्चों के विरुद्ध हाने वाले अपराधों से सम्बन्धित कई बार शोधकर्ताओं द्वारा पता लगाने की कोशिश की जा चुकी है लेकिन आज तक किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुँच पाना

असंभव जैसा प्रतीत होता है। लेकिन यदि घटित हुए अपराधों का अवलोकन करें तो ये जरूर कह सकते हैं कि बच्चों के विरुद्ध अपराध क्षेत्रों के अनुसार व उनके आस पास के वातावरण के अनुसार, उनकी पारिवारिक स्थिति, शैक्षणिक स्तर को भी देखने को मिलता है। कई बार बच्चों प्रति अपराध मात्र कुरीतियों की बजह से भी होते हैं। कुछ कारण निम्नलिखित हैं—

1. अधिकतर बच्चों प्रति अपराध कुरीतियों के कारण भी होते हैं। जिसकी बजह से जन्म लेने से पहले ही भ्रूण हत्या के रूप में भी देखने को मिलता है।
2. बच्चों में अपरिपक्व समझ भी इसका अपराधों का प्रमुख कारण हो सकती है, क्योंकि स्कूलों में अभी भी बच्चों को अपराधों के सम्बन्ध में कोई गतिविधि के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। विछले कुछ दशकों में यदि स्कूली शिक्षा का अवलोकन करें तो पायेंगे कि नैतिक शिक्षा नाम का एक विषय पढ़ाया जाता था लेकिन जब से कम्प्यूटर एवं तकनीकी का जामाना आ गया है। तब से केवल टेक्नोलॉजी पर ही ध्यान दिया जा रहा है। अभी तक कानूनी शिक्षा एवं अन्य प्रकार के अपराधों के कारणों से बच्चों को जागरूक करने का कोई भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया है।
3. आज के दौर में अपना घर चालाने एवं जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने के लिए माता-पिता दोनों को काम काज करना पड़ता है। जिसके कारण वह अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जिसके कारण भी बच्चे अपराधों का शिकार हो जाते हैं।
4. जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं। जिस कारण से भी बच्चों को देश दुनिया के बाँरें में जानकारी नहीं हो पाती है, और ये बच्चे कुछ असामाजिक तत्वों के आसानी से शिकार बन जाते हैं। और अपने प्रति होने वाले अपराधों का प्रतिरोध भी नहीं कर पाते हैं।
5. आज के दौर में परिवारों का एकाकी होते जाना भी इसका प्रमुख कारण है। क्योंकि जब संयुक्त परिवार होते थे तो माता-पिता के अलावा परिवार

* Corresponding author


E-mail: nitinmadhwani@rediffmail.com (Nitin Madhwani).

DOI: <https://doi.org/10.53724/ambition/v7n1.07>

Received 18th April 2022; Accepted 20th May 2022

Available online 30th May 2022

2456-0146 /© 2022 The Authors. Published by Research Ambition (Publisher: Welfare Universe). This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

 <https://orcid.org/0000-0001-5358-6293>



के दूसरे लोग भी बच्चों का ध्यान रखते थे। जिससे बच्चे संरक्षित रहते थे और परिवारों की संख्या अधिक होने से असामाजिक तत्वों का भी डर रहता था जिससे वे अपराध करने से भी हिचकिचाते थे।

6. बच्चों का भरण पोषण ठीक से न हो पाने के कारण भी इनका मानसिक स्तर भी कमजोर हो जाता है। जिसके कारण ये बच्चे सही व गलत का निर्णय नहीं कर पाते और अपराधों का शिकार हो जाते हैं।
7. अपराधों का जन्म देने में सबसे बड़ा कारण आस-पड़ोस का वातावरण होता है। जैसे चातावरण में व्यक्ति निवास करता है। वैसे ही उसके विचार बन जाते हैं। और जैसे व्यक्ति के विचार बनते हैं। वैसे ही वह कार्य करने लग जाता है।
8. कुछ अपराधियों द्वारा अश्लील साहित्य के जरिये भी बच्चों को अपराधों में लपेटने की कोशिश करते हैं और कई बार ये अपराधी कामयाब भी हो जाते हैं। कई बार पुलिस कार्यवाही में पोर्न फिल्में दिखाते हुये कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है।

बच्चों के विरुद्ध अपराधों के प्रकार

कई पुस्तकों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों को कई प्रकार से अंजाम दिया जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं—

1. बच्चों की हत्या करना
2. मद्यपान एवं मादक पदार्थों के सेवन की लत
3. यौन अपराध
4. कय-बिकय
5. बाल अपराधी बनाना
6. बाल मजदूरी एवं बंधुआ मजदूरी
7. अपहरण एवं व्यपहरण
8. बाल विवाह
9. क्रूरता या मानसिक अपराध
10. साईबर अपराध

1. बच्चों की हत्या करना

प्रति वर्ष कई बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है जिनमें बच्चों के शरीर पर से आभूषण एवं अन्य कीमती समान ले लेने के लिए भी इस तरह के अपराधों को अंजाम दे दिया जाता है। और कई बार तो बच्चों के द्वारा अपराधियों को अपराध करते देख लेने के कारण भी इनकी हत्या कर दी जाती है।

2. मद्यपान एवं मादक पदार्थों के सेवन की लत

बच्चें होते हैं मन के सच्चे इसलिए उनको जिस तरफ मोड़ देते हैं। उसी तरफ वो मुड़ जाते हैं। कई बार कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा अपने दो नम्बर के धन्धों को चलाने के लिए व अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी करने के लिए भी इन बच्चों का दुरुपयोग कर लेते हैं। जिस कारण से ये बच्चे थोड़े बहुत लालच में आ जाते हैं और अपराधों का शिकार हो जाते हैं।

3. यौन अपराध

आज के तकनीकी युग में लोग सबसे ज्यादा इन्टरनेट का उपयोग करके बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ आसामाजिक तत्वों के द्वारा इनका दुरुपयोग करके बच्चों को अश्लील फिल्मों को दिखाकर यौन अपराधों में लिप्त कर देते हैं। यह एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार कोई बच्चा यदि फँस जाता है तो कभी बहार नहीं निकल पाता है। क्योंकि समाज भी उसको हेय दृष्टि से देखने लगता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि उस बच्चें का जीवन ही बर्बाद हो जाता है।

4. कय-बिकय

बच्चों के कय-बिकय के लिए भले ही सरकार द्वारा कई कानून बनाकर अपराधों को रोकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इन अपराधों पर पूरी तरह से लगाम लगा पाना असंभव प्रतीत होता है। क्योंकि आज भी कई जगहों पर बच्चों के कय-बिकय घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है।

5. बाल अपराधी बनाना

वर्तमान समय में बच्चों के सुधार के लिए कानून बनाकर कई प्रकार की सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा कई प्रकार की हेल्पलाइन चलाई जा रही है। जिससे बच्चों को अच्छे कार्यों की तरफ अग्रसर किया जा सके। लेकिन फिर ऐसे बच्चे जो लाबारिस होते हैं या फिर कही से आयात किये गये हैं अपराधियों के द्वारा इनको लोभ लालच देकर अपराधिक गतिविधियों में लिप्त कर लेते हैं। और बच्चों के द्वारा किये जाने वाले अपराधों पर पुलिस का भी ध्यान कम जाता है। जिससे अपराधी आसानी से बच जाते हैं।

6. बाल मजदूरी एवं बंधुआ मजदूरी

बाल मजदूरी एवं बंधुआ मजदूरी भारतीय संविधान के द्वारा निषिद्ध कर दिया है

फिर कई जगह आज भी होटल, ढाबे, फैंट्रियों एवं शहरों में चाय की दुकानों में चाय बेचते हुए मिल जाते हैं। यदि भारतीय संविधान का अवलाकन करे तो अनु. 23 एवं 24 इसी सम्बन्ध में प्रावधान करता है।

7. अपहरण एवं व्यपहरण

अपहरण एवं व्यपहरण दोनों को ही भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार अपराध की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 में विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है। जिसमें यदि किसी नर बच्चें की उम्र 16 वर्ष से कम है, और यदि कोई नारी जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो और कोई व्यक्ति किसी बच्चे को बहला फुसलाकर ले जाता है। और उस बच्चे के संरक्षक की बिना सम्मति से तो भा.द.वि. की धारा 361 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। भा.द.वि. की धारा 362 के में अपहरण को परिभाषित किया गया है। अपहरण एवं व्यपहरण अलग-अलग प्रयोजन के लिए किये जाते हैं। जिसके प्रावधान भा.द.वि. की धारा 359 से 376ई तक किये गये हैं।

8. बाल विवाह

बाल विवाह एक भारत की विकराल समस्या है हालाँकि केन्द्र सरकार ने 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरसित कर दिया है एवं एक नया अधिनियम 2006 में पारित किया गया जो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 कहा जाता है। अधिनियम की धारा 12 के अनुसार यदि किसी बालक का विवाह जो प्राप्तवय नहीं है बहला फुसलाकर कर भी दिया जाता है। तो ऐसा विवाह शून्य होगा। यदि कोई बाल विवाह का अनुष्ठापन करता है तो 2 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना जो कि 1 लाख रुपये तक का हो सकता है। सरकार द्वारा इस प्रथा को रोकने की दिशा में उचित कदम उठाने की नहल की है। इसके अंतर्गत उन लोगों के खिलाफ कठोर उपाय किये गये हैं जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं।

9. क्रूरता या मानसिक अपराध

बच्चों की अच्छी शिक्षा और विकास के लिए सरकारों द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कही न कही ऐसी लोगों की मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि यदि बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना है तो उनको गलतियों के लिए शारीरिक प्रताड़ना देने से सुधारा जा सकता है। कई स्कूलों में भी यही रवैया अपनाया जाता है। लेकिन शिक्षा के अधिकार 2009 के लागू किये जाने के बाद धारा 17 द्वारा बच्चों को स्कूलों में प्रताड़ित करने के लिए प्रबन्धित किया है।¹ आज भी यदि ऐसे माता पिता जो कम शिक्षित हैं वो आज भी यही मानते हैं कि बच्चों को सुधारने के लिए उनकी गलतियों पर प्रताड़ित किया जाना चाहिये। लेकिन अब समय व परिस्थितियों के साथ-साथ सभी में बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

10. साईबर अपराध

साईबर अपराध बच्चों के प्रति सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। क्योंकि आज के दौर में प्रत्येक बच्चा किसी न किसी माध्यम से साईबर गजेट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ऑनलाइन क्लास और अन्य प्लेटफार्म के माध्यमों से विडियो देखकर बच्चे पढ़ाई करने लगे हैं। और जब से कोविड का दौर आया तब से अधिकतर बच्चों की ऑनलाइन पहुँच अधिक हो गयी है। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इन बच्चों को आसानी से शिकार बना लेते हैं। जिसका प्रमुख कारण ये भी है कि बच्चे अपरिपक्व समझ के होने के कारण उन अपराधियों के चंगुल में आसानी से फस जाते हैं।

बच्चों के विरुद्ध अपराधों के सम्बन्ध में कानूनी दृष्टिकोण

भारत में बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में कानूनी दृष्टिकोण हमेशा से सकारात्मक रहा है। जिसके लिए विधायिका द्वारा समय-समय पर बच्चों के हितों को संरक्षित करने के लिए कानूनों को पारित किया गया है। और ऐसे कानून जो पुराने हो गये हैं। जिनको समय के साथ बदल जाना चाहिये उनको बदला गया है एवं जिनमें संशोधन की आवश्यकता है उनमें आवश्यक संशोधन करने के बाद लागू किया गया है। जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:

1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012,
2. बालक श्रम (प्रतिषेध विनियमन) अधिनियम, 1986,
3. किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (संशोधित) 2000,
4. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006
5. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005
6. शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोटल एवं शिशु खाद्य (उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992
7. शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोटल एवं शिशु खाद्य (उत्पादन, आपूर्ति एवं

वितरण का विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2003

भारतीय न्यायिक दृष्टिकोण

भारतीय न्याय पालिका ने भी बच्चों के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से अहम भूमिका निभाई है। भारतीय संसद द्वारा अधिनियम बनाकर बच्चों को संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की है, लेकिन प्रश्न ये है कि उपर्युक्त अधिनियमों का कार्यान्वयन कैसे किया जाये। कानूनों को जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों से बच्चों को संरक्षण दिलाने के लिए कुछ वैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई है। यदि इन संस्थाओं द्वारा कानूनों को लागू करने में लापरवाही की जाती है। तो न्यायालयों द्वारा समय-समय पर मनमानी पूर्ण व्यवहार पर रोक लगाकर कानूनों व अन्य योजनाओं को सही प्रकार से लागू करने के लिए दिशानिर्देशों को जारी कर लागू करवाने के लिए एक पहल की जाती है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो कि निम्नलिखित हैं—

स्वपन कुमार साहा बनाम साउथ प्वाइंट मान्टेसरी हाई स्कूल और अन्य³ इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि स्कूल बसों में बच्चों को सुरक्षित यात्रा करने का मूल अधिकार है। और उस बस में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना उनके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

पीपुल्स यूनिन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ⁴

इस मामले में माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष से कम है उन्हें किसी भी जोखिम वाले कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा।

एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य⁵

इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने में एवं अन्य संकट पूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता।

उन्नीकृष्णन का वाद⁶

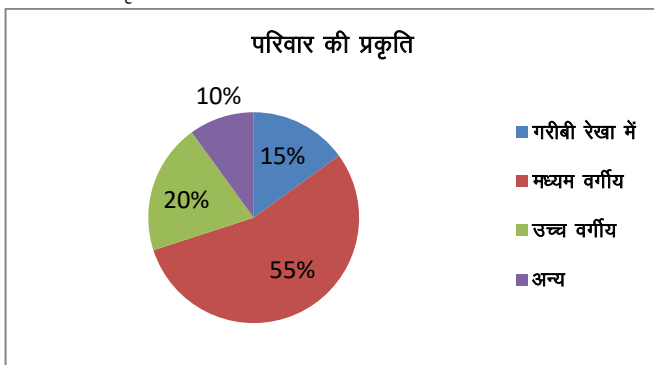
इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया। सभी ओर से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करने की माँग उठायी जाती रही है। इसके फलस्वरूप सरकार ने 86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बना दिया।

बच्चों के विरुद्ध अपराधों के सम्बन्ध में सामाजिक अध्ययन

बच्चों के विरुद्ध अपराधों के सम्बन्ध में सामाजिक अध्ययन करने के लिए इससे सम्बन्धित प्रश्नों/तारों के माध्यम से समाज के लोगों से जानने की कोशिश की गयी है कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में वे क्या सोचते हैं। जिसके सम्बन्ध में ऑनलाइन सर्वे गूगल फॉर्म के माध्यम से की गई है जिसके परिणाम निम्नलिखित हैं—

प्र. 01: आपके परिवार की प्रकृति क्या/कैसी है?

उ. 01: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 15.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति “गरीबी रेखा में” है। तथा 55.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति “मध्यम वर्गीय” है। और 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति “उच्च वर्गीय” है। और 10.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति “अन्य” है।

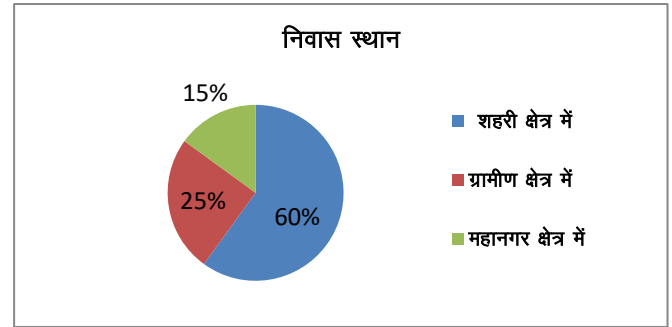


चित्र: 01

प्र. 02: आपका निवास स्थान कहाँ है?

उ. 02: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 60.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनका निवास “शहरी क्षेत्र में” है। तथा वही 25.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनका निवास “ग्रामीण क्षेत्र में” है। और वही 15.0 प्रतिशत

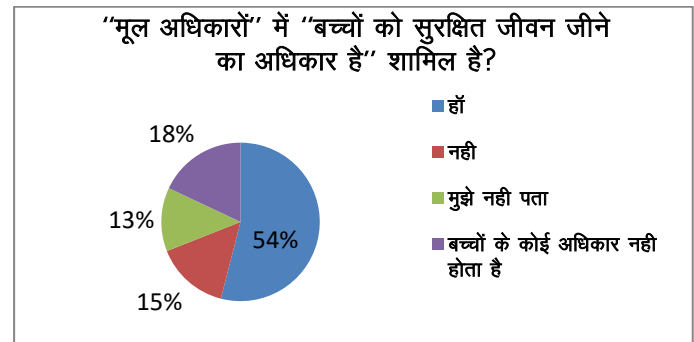
उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनका निवास “महानगर क्षेत्र में” है।



चित्र: 02

प्र. 03: क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त “मूल अधिकारों” में “बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है” भी शामिल है?

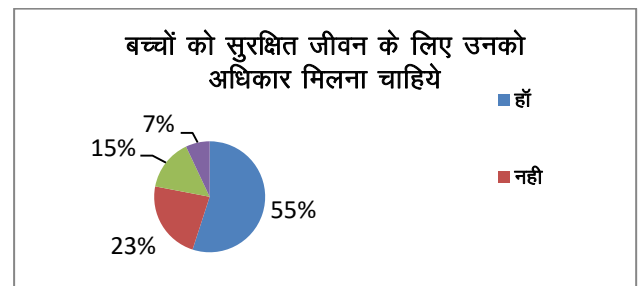
उ. 03: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 54.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि “मूल अधिकारों” में “बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है” शामिल है, और जिसका उत्तर “हाँ” में दिया। तथा 15.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि “मूल अधिकारों” में “बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है” शामिल नहीं है, और जिसका उत्तर “नहीं” में दिया। और 13.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि “मूल अधिकारों” में “बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है या नहीं” और जिसका उत्तर “मुझे नहीं पता” में दिया। और 18.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि “मूल अधिकारों” में “बच्चों को सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है” भी शामिल है या नहीं, और जिसका उत्तर “बच्चों के कोई अधिकार नहीं होता है” में दिया।



चित्र: 03

प्र. 04: क्या आप सहमत हैं कि बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए उनको अधिकार मिलना चाहिये?

उ. 04: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 55.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए उनको अधिकार मिलना चाहिये, जिसका उत्तर “हाँ” में दिया। तथा 23.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए उनको अधिकार तो मिलना चाहिये लेकिन उनका उपयोग समझदारी के साथ हो, जिसका उत्तर “नहीं” में दिया। और 15.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए उनको अधिकार मिलना चाहिये लेकिन अभिभावक की देख रेख में, जिसका उत्तर “अभिभावक की देख रेख में” में दिया। और 7.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया आज के दौर में बच्चे समझदार होते हैं, इसलिए बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए उनको अधिकार मिलना चाहिये, जिसका उत्तर “बच्चे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं” में दिया।



चित्र: 04

प्र. 05: क्या आप सहमत हैं कि बच्चों के विरुद्ध अपराध आज भी घटित होते

निष्कर्ष एवं सुझाव

उर्पयुक्त विवेचन और प्रश्नोत्तरों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों में कोई कारण नहीं है इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है उनकी समझ का अपरिपक्व होना जिसके कारण बच्चे अपने साथ होने वाले सही व गलत में भेद नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण आसानी से अपराधों के शिकार हो जाते हैं। और कई बार उनके अपनों लोगो के द्वारा ही उनका शोषण किया जाता है अग घरों की स्थिति में देखे तो बच्चों के द्वारा छोटे-मोटे कार्यों का किया जाना भी एक तरह का मानसिक व शारीरिक शोषण कह सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण असम्यक असर के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है। अब यदि स्कूलों की बात करे तो स्कूलों में भी भाग-दौड़ भरी जिन्दगी में प्रतिस्पर्धा को पूरा करने में बच्चों को आवश्यकता से अधिक काम दिया जाना और काम का पूरा न हाने की स्थिति में बच्चों की पिटाई करना व उनको डाटना आय दिन का काम हो गया है। लेकिन जब से शिक्षा का अधिकार कानून का निर्माण किया गया है जिसमें धारा 17 के अनुसार बच्चों की पिटाई को स्कूलों में प्रतिबन्धित किया गया है, तब से स्कूलों में कुछ सुधार देखने को मिलता है। लेकिन लगातार मॉनिटरिंग न होने की बजह से स्कूल अपने पुराने ढर्रे पर आ गये हैं। यदि घर से बहार की स्थिति का अवलोकन करे तो सभी जानते हैं कि कुछ असमाजिक तत्वों के द्वारा इनको मॉनिटर करने के बाद जैसे ही मौका मिलता है तो आसानी से शिकार बना लेते हैं। और ये बच्चे अपने

संदर्भ सूची

- ¹ किशोर अपराध: अवलोकन दिनांक 25 सितम्बर 2021: <https://hi.wikipedia.org/wiki/किशोर-अपराध>
- ² धारा 17: शिक्षा के अधिकार 2009।
- ³ AIR 2009 Rajasthan 63.
- ⁴ AIR 1983 SC1473.
- ⁵ (1996)6 SCC 756.
- ⁶ (1993)4 SCC 645.

माता- पिता के डर से कुछ कह भी नहीं पाते हैं।

उर्पयुक्त विवेचन के आधार पर सुझाव निम्नलिखित है-

1. सरकार को चाहिये की ऐसे नियम बनाये कि निश्चित अवधि के अन्तरालों में स्कूलों का निरीक्षण किया जाये एवं प्रत्येक स्कूल के बच्चों से इस सम्बन्ध में बातचीत करके पता किया जाये कि किसी भी प्रकार का शोषण या आपाधिक गतिविधियों तो नहीं चल रही है।
2. स्कूलों के अन्दर जो शरारती तत्व है उनकी काउंसिलिंग करके सुधारने की कोशिश करनी चाहिये।
3. सरकार को चाहिये कि ऐसे निकायों का गठन किया जाना चाहिये जो कि बच्चे के जन्म लेने लेकर उसके वयस्क होने तक निगरानी करे चाहे वो बच्चा कही पर भी रहे।
4. सरकार व ट्रेफिक पुलिस द्वारा लगभग सभी चौराहों पर सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाये गये हैं। उन कैमरों को उपयोग करके बच्चों व अन्य लोगों के साथ होने वाले अपराधों को रोका जा सकता है।
5. अपराध करने वाले अपराधियों की निजी जानकारी सरकार के पास पहले से ही आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध है। जिसका उपयोग करके अपराध करने वालों के ठिकानों का पता लगा कर तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है।